पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, प्रेम चंद पंडित, गुरदेव सिंह, एच. आर. सोढ़ी और बाल राज तुली, के समक्ष

बक्सी अमरीक सिंह– अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ–प्रतिवादी

1969 के आदेश संख्या 31 से पहली अपील

अक्टूबर 10, 1972

टॉर्ट्स का कानून–मालिक और नौकर–भारत का संविधान (1950)–अनुच्छेद 300 (1) -सरकारी कर्मचारियों के घृणित कृत्य–नुकसान के लिए राज्य का दायित्व–प्रकृति और सीमा–कहा गया है- सैन्य पुलिस के सदस्य ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच के लिए आगे बढ़ने के लिए तेजी से और लापरवाही से एक सैन्य वाहन चला रहे हैं–इस तरह की लापरवाही के कारण किसी नागरिक को लगी चोट - भारत संघ - चाहे नुकसान के लिए उत्तरदायी हो।

अभिनिर्धारित किया कि, (पूर्ण पीठ के अनुसार) कि अपने सेवकों के घृणित कृत्यों के लिए क्षति के लिए राज्य के दायित्व का निर्धारण करने के लिए कानून के प्रस्ताव और मार्गदर्शन के नियम निम्नलिखित हैं:

(1) भारत संघ और राज्य सरकार की सेवा में नौकरों की लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं यदि लापरवाही ऐसी है जो एक साधारण नियोक्ता को उत्तरदायी बनाती है।;

(2) राज्य उत्तरदायी नहीं है यदि शिकायत की गई कठोर कार्य उसके सेवकों द्वारा संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है, अर्थात ऐसी शक्तियां जिन्हें संप्रभु अधिकारों के प्रत्यायोजन के आधार पर एक संप्रभु या व्यक्ति के अलावा कानूनी रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है;

(3) सरकार अपने सेवकों या एजेंटों के उन घृणित कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है जो

उसके संप्रभु कार्यों के प्रयोग में या ऐसे लोक सेवकों को सौंपी गई संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए साबित नहीं हुए हैं।;

(4) केवल यह तथ्य कि शिकायत की गई कार्रवाई एक लोक सेवक द्वारा अपने रोजगार के दौरान की गई है, सरकार को इस तरह के कृत्य के कारण हुई चोट के लिए नुकसान के लिए दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।;

(5) जब राज्य अपने सेवकों के लापरवाह कार्य के कारण होने वाली चोट से होने वाले नुकसान के लिए प्रतिरक्षा के खिलाफ प्रतिरक्षा का अनुरोध करता है, तो संप्रभु शक्तियों को संदर्भित रोजगार के क्षेत्र को सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह की याचिका को बरकरार रखने से पहले, न्यायालय को हमेशा यह पता लगाना चाहिए कि लागू किया गया कार्य एक उपक्रम या रोजगार के दौरान किया गया था जो प्रत्यायोजित संप्रभु शक्तियों के प्रयोग के लिए संदर्भित है।;

(6) सरकार के संप्रभु कार्यों और गंभीर नहीं होने वाले कार्यों के बीच एक वास्तविक और स्पष्ट अंतर है, और बाद की श्रेणी में आने वाले कुछ कार्य व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय और औद्योगिक उपक्रमों से जुड़े हैं।;

(7) जहां वह रोजगार जिसमें कठोर कृत्य किया जाता है, ऐसा है जिसमें एक निजी व्यक्ति भी संलग्न हो सकता है, इसे एक संप्रभु कार्य या राज्य के प्रत्यायोजित संप्रभु कार्यों के दौरान किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है।;

(8) तथ्य यह है कि वाहन, जो दुर्घटना में शामिल है, सरकार के स्वामित्व में है और उसके नौकर द्वारा संचालित है, सरकार को इसकी तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। हालांकि यह साबित किया जाना चाहिए कि जिस समय दुर्घटना हुई, वाहन चलाने वाला व्यक्ति राज्य के संप्रभु कार्य, या ऐसे प्रत्यायोजित प्राधिकरण के निर्वहन में कार्य कर रहा था।;

(9) यद्यपि सेना का रख-रखाव भारत संघ का एक संप्रभु कार्य है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सेना के किसी कर्मी द्वारा किए गए किसी भी घृणित कार्य के लिए संघ सभी दायित्वों से मुक्त है।;

(10) यह निर्धारित करने में कि प्रतिरक्षा के दावे की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, अधिनियम की प्रकृति, जिस लेनदेन के दौरान यह किया गया है, इसे करने वाले व्यक्ति के रोजगार की प्रकृति और इसके लिए अवसर, सभी पर विचार किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 48)

अभिनिर्धारित किया कि, (पूर्ण पीठ के अनुसार) कि केवल एक सैन्य व्यक्ति को ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है. ड्यूटी पर तैनात सेना के कामकों की जांच एक ऐसा कार्य है जो सेना के अनुशासन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और यह केवल सशस्त्र बलों के एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है और वह भी उस बल के ऐसे सदस्य द्वारा जो इस तरह के कर्तव्य पर विस्तृत है और उस कार्य का निर्वहन करने के लिए सशक्त है। इसलिए, भारत संघ को सैन्य पुलिस के एक सदस्य द्वारा सेना के वाहन के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के परिणामस्वरूप किसी नागरिक को लगी चोटों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जो उसे सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा था।

(अनुच्छेद 50 और 52)

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित द्वारा 9 जनवरी, 1970 के आदेश के तहत मामले को पूर्ण पीठ को भेजा गया ताकि इसमें शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय लिया जा सके। 10 अक्टूबर, 1972 को माननीय न्यायमूर्ति डीके महाजन, माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित, माननीय न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह, माननीय न्यायमूर्ति एच आर सोढ़ी और माननीय न्यायमूर्ति श्री बाल राज तुली की पूर्ण पीठ द्वारा मामले और मामले का अंतिम निर्णय किया गया।

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अंबाला के दिनांक 2 दिसम्बर, 1968

के आदेश से प्रथम अपील में दावे के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

कुलदीप सिंह, कानून में बैरिस्टर, एल.एम. सूरी, आर.एस. मोंगिया, आर.एम. सूरी, और वी.पी. गांधी, अपीलकर्ता के लिए वकील.

जगन नाथ कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा और प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट अशोक भान.

निर्णय

गुरदेव सिंह, न्यायमूर्ति:

1. भारत संघ के खिलाफ अपीलकर्ता अमरीक सिंह के दावे को खारिज करने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अंबाला के दिनांक 21 फरवरी, 1968 के फैसले में से इस पूर्ण पीठ के विचार के लिए उठने वाले कानून के प्रश्न को इस प्रकार कहा जा सकता है:

   "क्या भारत सरकार सैन्य पुलिस में कार्यरत एक सिपाही द्वारा सेना के वाहन को तेज और लापरवाही से चलाने से एक निजी नागरिक को हुई चोट के लिए उत्तरदायी है, जिसमें वह ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा था?"

2. मामला निम्नलिखित तरीके से उठा है

3. अपीलकर्ता अमरीक सिंह 14 मई, 1967 को एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गए क्योंकि सैन्य ट्रक संख्या 10 के तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। अंबाला छावनी में एसएल-8085 पर सिपाही मान सिंह तैनात थे, जिन्हें पूरे दिन ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों की जांच करने के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने भारत सरकार से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का दावा किया, जिन्होंने उक्त सिपाही मान सिंह के खिलाफ तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के आरोप से इनकार करने के अलावा, इस दलील पर छूट का दावा किया कि चालक भारत संघ के संप्रभु कार्यों के निर्वहन में काम कर रहा था और इस प्रकार सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अंबाला ने पाया कि सिपाही मान सिंह द्वारा ट्रक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण अमरीक सिंह को चोटें आईं, लेकिन यह माना गया कि भारत संघ के खिलाफ

कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि सिपाही मान सिंह दुर्घटना के समय ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच करने के सैन्य कर्तव्य में लगे हुए थे। 21 फरवरी, 1968 के इस अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील करने पर, हमारे विद्वान भाई पी सी पंडित, जे. के समक्ष उठाया गया एकमात्र विवाद, जैसा कि उनके लॉर्डशिप के संदर्भ ति आदेश से स्पष्ट है, यह था कि जिस समय दुर्घटना हुई थी। सिपाही मान सिंह, जो सैन्य ट्रक चला रहा था, राज्य की किसी भी संप्रभु शक्तियों के निर्वहन में कार्य नहीं कर रहा था, जो भारत संघ को उसके द्वारा किए गए क्रूर कृत्य के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त कर देगा। हालांकि एक समय यह तर्क दिया गया था कि ट्रक का चालक निगार सिनेमा में सैन्य कर्मियों को छोड़ने के बाद यूनिट में लौट रहा था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को देखते हुए पीसी पंडित, जे के सामने यह स्वीकार किया गया कि दुर्घटना के समय सिपाही मान सिंह पूरे दिन ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों की जांच के लिए ड्यूटी पर थे। जो प्रवेश विशेष रूप से संदर्भ क्रम में भी दर्ज किया गया है।

4. इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश के विचारार्थ जो प्रश्न बचा था, वह यह था कि क्या सिपाही मान सिंह सरकार की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहा था और इन परिस्थितियों में, भारत संघ उसके द्वारा किए गए घृणित कृत्य के लिए सभी दायित्वों से मुक्त था। बहस के दौरान भारत संघ बनाम हरबंस सिंह और अन्य[1], मामले में इस न्यायालय के निर्णय और रूप राम कालू राम अग्रवाल बनाम पंजाब राज्य [2] और भारत संघ बनाम श्रीमती जस्सो[3], इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया गया था । रूप राम के मामले (2) को इस आधार पर अलग किया गया था कि यह सैन्य विभाग में कार्यरत व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से संबंधित नहीं था, जबकि अन्य पूर्ण पीठ मामले (भारत संघ बनाम श्रीमती जस्सो, (3)) में निर्धारित नियम की शुद्धता पर भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सवाल उठाय था। इस विचार के बाद कि इस प्रकार उत्पन्न हुए कानून के प्रश्न को अधिकारपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए, हमारे विद्वान भाई पी. सी. पंडित, जे. ने निर्देश

[1] ए.आई.आर. 1959 पी.बी. 39-61 पी.एल.आर.

[2] ए.आई.आर. 1961 पी.बी. 336.

[3] ए.आई.आर. 1962 पी.बी. 315.

दिया कि मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जाए। इस प्रकार यह मामला इस पूर्ण पीठ के समक्ष आया है।

5. यद्यपि पूरी अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, लेकिन इसका हश्र इस आदेश के शुरुआती भाग में उल्लिखित कानून के प्रश्न पर निर्भर करता है, जो अपने सेवकों के घृणित कृत्यों के लिए भारत संघ के दायित्व से संबंधित है, क्योंकि संदर्भ का आदेश दिए जाने के समय यह अकेले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए बच गया था।

6. यह कानून का एक स्थापित और निर्विवाद सिद्धांत है कि मालिक अपने सेवक के हर ऐसे गलत के लिए जवाबदेह है जो उसकी सेवा के दौरान किया जाता है, हालांकि मालिक का कोई स्पष्ट आदेश या गोपनीयता साबित नहीं की जा सकती है और गलत कार्य मालिक के लाभ के लिए नहीं हो सकता है। वास्तव में, इस प्रस्ताव के लिए भी प्राधिकार की एक श्रेणी है कि यद्यपि कार्रवाई का कारण बताने वाला विशेष कार्य अधिकृत नहीं हो सकता है, फिर भी, यदि कार्य रोजगार के दौरान किया जाता है जो अधिकृत है, तो मास्टर उत्तरदायी है। इस संबंध में सिटिजंस लाइफ एश्योरेंस कंपनी बनाम ब्राउन[4], माचे बनाम न्यू ब्रंसविक के वाणिज्यिक बैंक[5], और ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एम. एम. शेराजी[6], को संदर्भित करना पर्याप्त होगा। गाह चून सेंग बनाम ली किम सू[7], यह फैसला सुनाया गया है कि जब कोई नौकर ऐसा कार्य करता है जिसे उसके नियोक्ता द्वारा कुछ परिस्थितियों में और कुछ शर्तों के तहत करने के लिए अधिकृत किया जाता है और वह उन्हें परिस्थितियों में या इस तरह से करता है जो अनधिकृत और अनुचित है, यहां तक कि ऐसे मामलों में भी नियोक्ता गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है।

7. अपने सेवक के कृत्यों के लिए स्वामी के दायित्व का यह सिद्धांत अधिकतम उत्तरदाता श्रेष्ठ पर आधारित है, जिसका अर्थ है 'सिद्धांत को उत्तरदायी होने दें' और यह मालिक को उसी स्थिति में रखता है जैसे कि उसने स्वयं कार्य किया हो। यह प्रति एलियम फैसिट प्रति अधिकतम

[4] (1904) ए. सी. 423.
[5] (1874) एल. आर. 5 पी. सी. 394.
[6] (1878) आईए 130
[7] (1925) ए.सी. 550.

क्यूसीट से वैधता भी प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि 'जो कोई दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, उसे कानून में स्वयं करने के लिए समझा जाता है'। सच्चा सिद्धांत, जैसा कि रतन लाल ने अपनी पुस्तक द 1 इंडियन एंड इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट्स के 19 वें संस्करण के पृष्ठ 79 पर कहा है, यह है:

"एक व्यक्ति जो अपनी अनुपस्थिति में कृत्यों के एक वर्ग को करने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य को रखता है, आवश्यक रूप से उसे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करने के लिए छोड़ देता है, जब उस वर्ग का कोई कार्य किया जाना है, और जिस तरीके से यह किया जाता है उसके लिए उस पर भरोसा करता है; नतीजतन, वह उस व्यक्ति की गलती के लिए जवाबदेह होता है जिसे इस तरह के कार्य को करने के तरीके में सौंपा गया है, या ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कार्य करना जिसमें ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था; बशर्ते कि जो किया जाता है वह नौकर के किसी भी वेतन से नहीं, बल्कि रोजगार के दौरान किया जाता है।"

अपने नौकर के कृत्यों के लिए मालिक के दायित्व के संबंध में कानून के सामान्य सिद्धांत, जैसा कि ऊपर संक्षेप में बताया गया है, हमारे सामने पेश नहीं किए गए हैं और यह स्वीकार किया जाता है कि यदि सिपाही मान सिंह दुर्घटना के समय एक निजी व्यक्ति के रोजगार में था, न कि भारत संघ या राज्य और अपने कर्तव्य के दौरान गाड़ी चला रहा था, उसका नियोक्ता निश्चित रूप से अपीलकर्ता को उसके द्वारा लगी चोटों के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। भारत संघ की ओर से पेश हुए हरियाणा के महाधिवक्ता ने हालांकि आग्रह किया है कि चूंकि दुर्घटना तब हुई थी जब सिपाही मान सिंह सैन्य ड्यूटी में लगे हुए थे, जो एक संप्रभु कार्य है, इसलिए भारत संघ उनके तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए सभी दायित्वों से मुक्त है। इस संबंध में मेसर्स कस्तूरी लाल रालिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[8] में उच्चतम न्यायालय के फैसले और भारत संघ बनाम हरबंस सिंह और अन्य (1), मामले में खंडपीठ के निर्णय के अलावा विभिन्न न्यायालयों के कई अन्य प्राधिकरणों पर भरोसा रखा गया है। बाद के मामले में इस अदालत द्वारा यह माना गया था कि भारत संघ सैन्य विभाग के

[8] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1039.

एक ट्रक के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए उत्तरदायी नहीं था, जबकि चालक ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों को भोजन की आपूर्ति करने के सैन्य कर्तव्य में लगा हुआ था।

8. इसके विपरीत, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो पूर्ण पीठ के फैसलों का हवाला दिया है। रूप राम बनाम पंजाब राज्य (2), पूर्ण पीठ (जीडी खोसला, सीजे, एसएस दुलत और हरबंस सिंह, जेजे) ने फैसला सुनाया कि राज्य केवल इसलिए दायित्व से पूरी तरह से मुक्त नहीं है क्योंकि शिकायत की गई कार्रवाई उसकी सरकारी या कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करके की गई हो सकती है, और यह देखा जाना चाहिए कि क्या वही कारण हैं, जो एक अदालत को नियोक्ता पर दायित्व तय करने के लिए प्रेरित करेगा, मौजूद है या नहीं। उस मामले में आगे यह देखा गया कि यदि यह प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा नियोजित एक सेवक ने राज्य के लाभ के लिए काम किया था और इस प्रक्रिया में उसने एक अपराध किया था, तो राज्य नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। उस विशेष मामले में लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक ट्रक ने विभाग के रोजगार में चालक द्वारा संचालित एक मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने से चोटें आईं। पूर्ण पीठ ने कहा कि ट्रक के चालक के नियोक्ता, हालांकि राज्य को, अपने रोजगार के दौरान किए गए अपने लापरवाह कृत्य के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए जैसा कि सामान्य नियोक्ता करता है और तथ्य यह है कि लोक निर्माण विभाग इस अर्थ में एक वाणिज्यिक विभाग नहीं था कि यह लाभ कमाने से संबंधित नहीं था। कोई मदद। बाद में, इस न्यायालय की एक और पूर्ण पीठ को (न्यायमूर्ति डी. फलशॉ, मेहर सिंह और ए. एन. ग्रोवर) भारत संघ बनाम श्रीमती जस्सो (3), मामले में एक सैन्य चालक की जिम्मेदारी से निपटने के लिए बुलाया गया था, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिमला में जनरल मुख्यालय में कोयला ले जाते समय, तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण दुर्घटना का कारण बना। रूप राम बनाम पंजाब राज्य(2) मामले में पूर्व पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित नियम पर ध्यान दिया गया था, लेकिन माउंट विद्यावती बनाम लोकुमल[9], मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ

[9] ए. आई. आर. 1957 राज 305.

के निर्णय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। एक ऐसा मामला जिसे पिछली पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था:

"आमतौर पर संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए कृत्यों और उपक्रमों के संचालन में किए गए कृत्यों के बीच एक बड़ा और स्पष्ट अंतर है जो निजी व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है।".

9. इस उद्धरण के बाद फालशॉ, जे (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) ने पूर्ण पीठ की राय को रिकॉर्ड किया, निम्नानुसार देखा गया:–

"इस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हुए यह देखना मुश्किल है कि यह कैसे माना जा सकता है कि संभवतः कमरों को गर्म करने के उद्देश्य से शिमला में सामान्य मुख्यालय की इमारत में कोयले से भरे ट्रक को चलाने जैसे नियमित कार्य एक संप्रभु शक्ति का प्रयोग करके किया जाता है क्योंकि ऐसा काम स्पष्ट रूप से एक निजी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस तरह का मामला होने के नाते, मुझे नहीं लगता कि केवल यह तथ्य कि ट्रक सेना का ट्रक था और चालक एक सैन्य कर्मचारी था, चालक के क्रूर कृत्य के लिए नुकसान के लिए सरकार की देयता में कोई अंतर पैदा कर सकता है।

10. पीठ का पिछला फैसला, जिसमें वह खुद भी एक पक्ष थे, इन शब्दों से अलग था :

"जैसा कि मैंने पहले देखा है, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मेरे विद्वान भाइयों को कोई कठिनाई महसूस हुई होगी, लेकिन हरबंस सिंह (1) के मामले में निर्णय के लिए, जिसमें एक सैन्य ट्रक शामिल था और जिसमें उस मामले के अजीब तथ्यों पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चालक एक संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर रहा था और कुछ ऐसा कर रहा था जो निजी द्वारा नहीं किया जा सकता था। व्यक्तियों। उस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि ट्रक सैन्य कर्तव्यों पर लगे सेना के जवानों की जरूरतों की आपूर्ति के लिए चलाया जा रहा था जो नागरिकों द्वारा नहीं किया जा सकता था।

यह कहना किसी भी दर पर सुरक्षित है कि उस मामले को इस सामान्य प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि किसी भी मामले में सरकार के खिलाफ

नुकसान की कार्रवाई केवल इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि दुर्घटना में शामिल वाहन सेना का ट्रक है जिसे किसी सैन्य कर्मचारी द्वारा किसी ड्यूटी या अन्य के प्रदर्शन में चलाया जाता है।."

11. उपरोक्त उल्लिखित इस न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा करने के अलावा, अपीलकर्ता की ओर से पेश श्री कुलदीप सिंह ने अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों के कई अधिकारियों का हवाला दिया है कि भारत सरकार सिपाही मान सिंह द्वारा ट्रक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण अपीलकर्ता को लगी चोटों के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। जैसा कि प्रकाश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[10], उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा देखा गया है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर एक अधिकार है और तथ्यों पर कोई भी दो मामले समान नहीं हैं। इस प्रकार, हमारे सामने उद्धृत किए गए विभिन्न निर्णय अपने स्वयं के अजीबोगरीब तथ्यों पर मुड़ते हैं और इनमें से अधिकांश मामलों में पहुंचे निष्कर्षों को तथ्यों पर उचित ठहराया जा सकता है।

12. अपने नौकरों के घृणित कृत्यों के लिए एक नियोक्ता की देयता को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए थे और उनके बारे में पार्टियों के विद्वान वकील के बीच बहुत विवाद नहीं है। हरियाणा के महाधिवक्ता ने इस दलील पर भारत संघ के लिए प्रतिरक्षा का दावा किया कि सिपाही मान सिंह ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, जो उन्हें राज्य के संप्रभु कार्यों के संबंध में सौंपा गया था और तदनुसार, इस तरह के कर्तव्य के दौरान किए गए एक क्रूर कार्य के लिए क्षतिपूर्ति के लिए कोई मुकदमा या कार्यवाही भारत संघ के खिलाफ नहीं है। इस प्रकार यह जांच करना आवश्यक हो जाता है कि क्या भारत संघ को कोई प्रतिरक्षा प्राप्त है और यदि हां, तो इसकी सीमा क्या है।

13. भारत सरकार और राज्यों के विरुद्ध मुकदमों और कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 में निहित हैं, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

[10] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 195.

"300(1) भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा दायर कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है और किसी राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा या मुकदमा दायर कर सकती है और संसद के अधिनियम या इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित ऐसे राज्य के विधान-मंडल के किसी भी प्रावधान के अधीन रहते हुए, इस तरह के मामलों में अपने संबंधित मामलों के संबंध में मुकदमा दायर किया जा सकता है या मुकदमा दायर किया जा सकता है जैसे कि भारत और संबंधित प्रांतों या संबंधित भारतीय राज्यों ने मुकदमा दायर किया होगा या मुकदमा दायर किया जा सकता है यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया था।"

14. जैसा कि पंजाब राज्य बनाम ओ.जी.बी. सिंडिकेट लिमिटेड[11] मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा कहा गया है। यह अनुच्छेद कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म नहीं देता है, बल्कि केवल यह कहता है कि राज्य उन मामलों में एक न्यायिक व्यक्तित्व के रूप में मुकदमा कर सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है जहां सरकार के खिलाफ मुकदमा होगा, अगर संविधान अधिनियमित नहीं किया गया था, लेकिन कानून के अधीन था। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि अभी तक ऐसा कोई विधान अधिनियमित नहीं किया गया है। इस प्रावधान के दायरे और उद्देश्य से निपटने में, अनुच्छेद 300 (1), सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने मेसर्स कस्तूरी लाल रालिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (8) में निम्नानुसार टिप्पणी की।

"यह ध्यान दिया जाएगा कि इस अनुच्छेद (300) में तीन भाग हैं।

पहला भाग भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसके खिलाफ दायर किए जाने वाले मुकदमे के लिए फॉर्म और कारण-शीर्षक के बारे में प्रश्न से संबंधित है। दूसरे भाग में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि कोई राज्य अपने मामलों के संबंध में उन मामलों में मुकदमा कर सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है जिनमें संविधान अधिनियमित नहीं किए जाने पर संबंधित प्रांत ने मुकदमा दायर किया होगा या मुकदमा दायर किया होगा। दूसरे शब्दों में, जब यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य की सरकार

[11] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 669.

के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है, तो जांच की जानी चाहिए; यदि संविधान पारित नहीं किया गया होता तो क्या तदनुरूपी प्रांत के विरुद्ध ऐसा मुकदमा दायर किया जा सकता था? अनुच्छेद के तीसरे भाग में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 300 (1) द्वारा कवर किए गए विषय के संबंध में उचित प्रावधान करने के लिए संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए सक्षम होगा। चूंकि वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है, इसलिए यह सवाल कि क्या प्रतिवादी अपीलकर्ता के कहने पर नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने के लिए उत्तरदायी है, एक अन्य प्रश्न के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए और वह यह है कि क्या ऐसा मुकदमा संबंधित प्रांत के खिलाफ सक्षम होगा।

यह अंतिम जांच अनिवार्य रूप से हमें भारत के संबंधित संविधान अधिनियमों में संबंधित कार्यवाही प्रावधानों पर ले जाती है; वे भारत सरकार अधिनियम, 1858 की धारा 65 हैं; भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 32 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 176। 1858 के अधिनियम की धारा 65 से परे इस प्रावधान की वंशावली का पता लगाना अनावश्यक है, क्योंकि इस बिंदु पर संबंधित निर्णय, जिन्हें हम वर्तमान में संदर्भित करेंगे, अंततः उक्त धारा में निहित प्रावधानों के प्रभाव पर आधारित पाए जाते हैं।."

15. भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों के संगत उपबंधों की जांच करने के पश्चात् यह निर्णय दिया गया है कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत भारत संघ अथवा राज्य सरकारों पर केवल उसी कठोर कृत्य के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसकी शिकायत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई क्षति के लिए की गई होगी। इस प्रकार, यह पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नौकरों के घृणित कृत्यों के लिए किस हद तक उत्तरदायी थी। यह प्रश्न वर्ष 1861 में प्रायद्वीपीय और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम इन एंड ए-इन-कॉनोइल के लिए राज्य सचिव[12], में तत्कालीन कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। जिसका प्रमुख नोट पढ़ता है:

[12] 5 बीएम. एचसीआर ऐप. ए -एल.

"भारतीय परिषद में राज्य सचिव सरकार की सेवा में नौकरों की लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी है यदि लापरवाही ऐसी है जो एक साधारण नियोक्ता को उत्तरदायी बनाती है।."

16. यह वह मूल प्राधिकार है जिस पर इस विषय पर पूरा मामला-कानून आगे बढ़ता है और इसे कस्तूरी लाल (8) के मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उस मामले में जो निर्धारित किया गया है, उसकी सराहना करने के लिए, इसके तथ्यों को संदर्भित करना आवश्यक है, जो संक्षेप में ये हैं।:

17. कंपनी का एक नौकर किद्दरपुर डॉकयार्ड के माध्यम से एक राजमार्ग पर घोड़ों की एक जोड़ी द्वारा खींची गई गाड़ी में आगे बढ़ रहा था, जिसे पूरी तरह से सरकार की सेवा में व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया गया था, जब सरकारी कर्मचारी के कामगार, जो लगभग 9 फीट लंबे भारी लोहे के फ़नल आवरण का एक टुकड़ा ले जा रहे थे, ने वादी की गाड़ी के रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए अचानक इसे सड़क पर गिरा दिया। इस प्रकार लोहे के आवरण के गिरने के कारण होने वाले शोर ने वादी के घोड़ों को चौंका दिया, जो हिंसक रूप से आगे बढ़े, और लोहे पर गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक को नुकसान हुआ। वादी-कंपनी ने इस दुर्घटना से हुए नुकसान के लिए भारत के राज्य सचिव के खिलाफ मुआवजे का दावा किया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के लिए परिषद में राज्य सचिव सरकार की सेवा में नौकरों की लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा यदि लापरवाही ऐसी थी जो एक साधारण नियोक्ता को उत्तरदायी बनाती है।

18. भारत सरकार अधिनियम, 1858 की धारा 65 के आलोक में स्थिति की जांच करते हुए, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप ने पाया कि यदि दुर्घटना सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरदायी होगी और राज्य सचिव के साथ भी यही दायित्व जुड़ा होगा। जो भारत के राजस्व से संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुकदमा दायर करने के लिए उत्तरदायी था। पीकॉक, चीफ जस्टिस, न्यायालय का निर्णय देते हुए रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर इस प्रकार देखा गया :

"इस सवाल का निर्धारण करने में कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, इन परिस्थितियों में, कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी, संप्रभु और राज्यों पर लागू सामान्य सिद्धांत, और अंग्रेजी कानून के मैक्सिम से यह तर्क कि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, का कोई बल नहीं होगा। हम बैंक ऑफ बंगाल बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी[13], मामले में मुख्य न्यायाधीश ग्रे द्वारा व्यक्त की गई राय से पूरी तरह सहमत हैं। जिसे तर्क में उद्धृत किया गया था, कि कंपनी के उन शक्तियों के साथ निवेश किया गया था जिन्हें आमतौर पर संप्रभु शक्तियां कहा जाता है, उन्हें संप्रभु नहीं बनाती है।

19. इस मामले में आगे बढ़ते हुए मुखिया नायधीश ने कहा पृष्ठ 12 पर कहा:

"अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार के उद्देश्य से, बैलगाड़ी और किराए के लिए माल और यात्रियों के परिवहन जैसे उपक्रमों में संलग्न होने की अनुमति दी गई थी, तो यह उचित था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, व्यक्तियों के समान देनदारियों के अधीन। यदि, उन्हें सरकार की शक्तियां सौंपे जाने के कारण, उन्हें व्यवसाय के मामलों में व्यक्तियों के सामान्य दायित्व से छूट दी गई थी, या तो अपने स्वयं के लाभ के लिए, जैसा कि एक समय में था, या सरकार के प्रयोजनों के लिए, जैसा कि दूसरे समय में था, निजी व्यक्तियों को उनके साथ बहुत ही हानिकारक शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती।"

फिर पृष्ठ 13 पर लॉर्डशिप ने आगे कहा:

"हमारी राय है कि इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए, यदि सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे और चौथे डब्ल्यूएम से पहले और बाद में दोनों के लिए उत्तरदायी होगी। हमारी राय है कि यह न केवल शब्दों के भीतर, बल्कि तीसरे और चौथे डब्ल्यूएम IV, c.85, s.9, और 21 वें और 22 वें वियतनाम, c.106, s.65 की भावना के भीतर भी एक दायित्व है, और यह सामान्य <u>ज्ञान और न्याय</u> के साथ असंगत होगा।

20. इस प्रश्न से निपटते हुए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी संप्रभु थी या नहीं, यह देखा गया:

[13] बिगनेल, रेप् . प. 120.

"हमारी यह भी राय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी संप्रभु नहीं थी, और इसलिए, एक संप्रभु की सभी छूट का दावा नहीं कर सकती थी और वे सरकार के लोक सेवक नहीं थे, और इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की देनदारियों के संबंध में मामलों के सिद्धांत के तहत नहीं आते थे, लेकिन वे एक ऐसी कंपनी थे जिन्हें संप्रभु शक्तियां सौंपी गई थीं, और जो अपने स्वयं के खाते पर और अपने स्वयं के लाभ के लिए व्यापार करते थे, और आंशिक रूप से सरकार के प्रयोजनों के लिए लेनदेन में लगे हुए थे, और आंशिक रूप से अपने स्वयं के खाते पर, जो संप्रभु अधिकारों के किसी भी प्रतिनिधिमंडल के बिना, निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था। आमतौर पर संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए कृत्यों और उपक्रमों के संचालन में किए गए कार्यों के बीच एक बड़ा और स्पष्ट अंतर है, जो निजी व्यक्तियों द्वारा ऐसी शक्तियों को सौंपे बिना किए जा सकते हैं: मूडले बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, और वही बनाम मॉर्टन[14]।

21. इसके बाद मूडले (14) के मामले में लॉर्ड केन्योन के बाद रोल्स के मास्टर की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया, जिन्होंने कहा था:

"मैं स्वीकार करता हूं कि उस क्षमता में किए गए किसी भी काम के लिए एक संप्रभु शक्ति के खिलाफ इस अदालत में कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईस्ट इंडिया कंपनी नियम के भीतर है। उनके पास एक संप्रभु शक्ति के रूप में अधिकार हैं; उनके पास व्यक्तियों के रूप में भी कर्तव्य हैं। यदि वे भारत में बांड में प्रवेश करते हैं, तो सुरक्षित राशि यहां वसूल की जा सकती है: इसलिए इस मामले में एक निजी कंपनी के रूप में उन्होंने एक निजी अनुबंध में प्रवेश किया है, जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए। यहां प्रथम दृष्टया कार्रवाई का आधार है: कंपनी ने वादी को चोट पहुंचाने के रास्ते में अन्य व्यक्तियों को डाल दिया है।

विभिन्न निर्णयों के आलोक में मामले की जांच करने के बाद, पीकॉक, सीजे ने इन शब्दों में कानूनी स्थिति बताई:

"... . जहां एक कार्य किया जाता है, या एक अनुबंध में प्रवेश किया जाता है, शक्तियों के प्रयोग

14

में आमतौर पर संप्रभु शक्तियां कहा जाता है, जिसके द्वारा हमारा मतलब उन शक्तियों से है जिन्हें कानूनी रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है

एक संप्रभु या निजी व्यक्ति को छोड़कर, जिसे एक संप्रभु द्वारा उनका उपयोग करने के लिए सौंपा गया है, कोई भी कार्रवाई झूठ नहीं होगी।

22. कस्तूरी लाल (8) के मामले में न्यायालय का निर्णय सुनाने वाले पीकॉक, प्रमुख न्यायधीश, गजेंद्रगडकर, प्रमुख न्यायधीश के फैसले की विस्तृत जांच के बाद इस उक्ति से निपटते हुए ने कहा:

पीठ ने कहा, 'मामले के इस पहलू के संबंध में प्रधान न्यायाधीश ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका बाद के सभी फैसलों में लगातार पालन किया गया. विद्वान सीजे ने कहा, 'आमतौर पर संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए कृत्यों और उपक्रमों के संचालन में किए गए कार्यों के बीच एक बड़ा और स्पष्ट अंतर है, जो निजी व्यक्तियों द्वारा ऐसी शक्तियों को सौंपे बिना किए जा सकते हैं। इस प्रकार मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने एक और प्रस्ताव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 'जहां कोई कार्य किया जाता है, या एक अनुबंध में प्रवेश किया जाता है, आमतौर पर संप्रभु शक्तियों के रूप में जानी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा मतलब उन शक्तियों से है जो संप्रभु या संप्रभु द्वारा सौंपे गए निजी व्यक्ति को छोड़कर कानूनी रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कोई कार्रवाई झूठ नहीं होगी'। और, स्वाभाविक रूप से यह इस प्रकार है कि जहां कोई कार्य किया जाता है, या एक अनुबंध में प्रवेश किया जाता है, शक्तियों के प्रयोग में, जिसे संप्रभु शक्तियां नहीं कहा जा सकता है, कार्रवाई होगी। संक्षेप में, प्रायद्वीपीय और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कं, (12) के मामले में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यही है।

23. इसके बाद लॉर्डशिप ने कानूनी स्थिति को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया क्योंकि यह इस प्राधिकरण से उभरता है:

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह मामला राज्य द्वारा नियोजित कर्मचारियों द्वारा किए गए

कृत्यों के बीच एक भौतिक अंतर को मान्यता देता है, जहां ऐसे कार्य लोक सेवकों को सौंपी गई संप्रभु शक्तियों के प्रयोग के लिए संदर्भित हैं, और लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्य जो किसी भी संप्रभु शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए संदर्भित नहीं हैं। यदि किसी लोक सेवक द्वारा कोई घृणित कृत्य किया जाता है और इससे क्षतिपूर्ति के दावे को बल मिलता है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या लोक सेवक द्वारा सांविधिक कार्यों के निर्वहन में किया गया क्रूर कार्य था, जो राज्य की संप्रभु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है, और अंततः ऐसे लोक सेवक को सौंप दिया गया है? यदि उत्तर हां में है, तो इस तरह के घृणित कृत्य के कारण होने वाले नुकसान के लिए नुकसान की कार्रवाई झूठ नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि किसी लोक सेवक द्वारा किसी संप्रभु शक्ति के प्रत्यायोजन के आधार पर उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में क्रूर कार्य किया गया है, तो नुकसान के लिए कार्रवाई की जाएगी। अपने रोजगार के दौरान उसके द्वारा किया गया लोक सेवक का कार्य, इस श्रेणी के मामलों में, उस नौकर का कार्य है जिसे उसी उद्देश्य के लिए एक निजी व्यक्ति द्वारा नियोजित किया गया हो सकता है। यह भेद जो कानून में स्पष्ट और सटीक है, कभी-कभी लोक सेवकों द्वारा किए गए क्रूर कृत्यों से उत्पन्न राज्य की देयता के सवालों पर चर्चा करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि 1861 की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश पीकॉक द्वारा जिस स्पष्टता और सटीकता के साथ इस भेद पर जोर दिया गया था, उसे इस विषय पर एक क्लासिक बयान के रूप में मान्यता दी गई है।

24. गजेंद्रगडकर, प्रमुख न्यायधीश, ने इसके बाद परिषद में भारत के राज्य सचिव बनाम मोमेंट[15] , शिवभजन दुर्गाप्रसाद बनाम भारत के राज्य सचिव[16], परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव बनाम ए. कॉकक्राफ्ट[17], परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव बनाम श्रीगोबिंदा चौधरी[18], मोहम्मद मुराद इब्राहिम खान बनाम संयुक्त प्रांत की सरकार[19] और उमा प्रसाद बनाम राज्य

[15] 40 आई.ए 48 (पी.सी.).
[16] आई.एल.आर. 28 बोम. 314.
[17] आई.एल.आर. 39 मैड 351-ए.आई.आर. 1915 मैड. 993.
[18] आई.एल.आर. 59 कैल. 1289.
[19] आई.एल.आर. (1957) 1 इला 94.

सचिव[20], प्रतिनिधि निर्णयों के रूप में को संदर्भित किया, जिसमें प्रायद्वीपीय और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी के मामले (12) में पीकॉक, प्रमुख न्यायधीश, द्वारा प्रतिपादित 'मूल सिद्धांत' का लोक सेवकों द्वारा किए गए लापरवाह य क्रूर कृत्यों के संबंध में राज्य के दायित्व से निपटने में लगातार पालन किया गया था।

25. यहां यह देखा जा सकता है कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उमा पारशाद (20) के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय के अलावा इनमें से किसी भी फैसले पर टिप्पणी नहीं की, जिसके संबंध में, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्षों के समर्थन में दिए गए कुछ कारण संदेह के लिए खुले हो सकते हैं, लॉर्डशिप ने कहा।

यह निर्णय इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि नुकसान के दावे को जन्म देने वाला कार्य एक लोक सेवक द्वारा किया गया था, जिसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक क़ानून द्वारा अधिकृत किया गया था, और उक्त कार्य के निर्वहन को राज्य की संप्रभु शक्ति के प्रत्यायोजन को संदर्भित किया जा सकता है, और इस तरह आपराधिक कृत्य जिसने कार्रवाई को जन्म दिया, राज्य के खिलाफ नुकसान के लिए वैध रूप से दावा नहीं कर सका।

26. इस प्रकार इसे आधिकारिक रूप से तय किया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 300 (1) के तहत, भारत संघ और हमारे गणराज्य में राज्यों का अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए मुकदमा दायर करने का वही दायित्व है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था।

27. ईस्ट इंडिया कंपनी की देयता की प्रकृति और सीमा, जैसा कि पहले देखा गया है, नौकरों के क्रूर कृत्यों के लिए वर्ष 1861 में तय किया गया था और उस बिंदु पर कानून, जैसा कि द पेनिनसुलर एंड स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव (12), में विद्वान पीकॉक, सीजे द्वारा कहा गया था, अभी भी मैदान में हैं। वह दृष्टिकोण यह है कि सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी है यदि लापरवाही ऐसी है जो एक साधारण नियोक्ता को इस तरह के नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाती है और इसके बाद आवश्यक निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्य उत्तरदायी नहीं है यदि राज्य के संप्रभु कार्यों के

[20] आई.एल.आर. (1937) 18 लाह. 380.

निर्वहन में उसके सेवकों द्वारा शिकायत किए गए कठोर कृत्य किए गए हैं। कानून का यह शासन राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती विद्यावती और एक अन्य[21], और मेसर्स कस्तूरी लाल रालिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (8), जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से तय होता है। बाद के निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि वैधानिक कार्यों के निर्वहन में एक लोक सेवक द्वारा किए गए कृत्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जो ऐसे लोक सेवक को राज्य की संप्रभु शक्तियों के प्रत्यायोजन पर संदर्भित और अंततः आधारित हैं, और उसके रोजगार के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य जो राज्य की किसी भी संप्रभु शक्तियों के निर्वहन में नहीं हैं और जो हो सकते थे। एक नौकर द्वारा किया गया जो एक निजी व्यक्ति द्वारा उसी उद्देश्य के लिए नियोजित किया गया हो सकता है। दायित्व का निर्धारण करने के लिए, हमें उस कर्तव्य की प्रकृति और गुणवत्ता को देखना होगा जिसके दौरान शिकायत की गई है। इस संबंध में, मैसर्स कस्तूरी लाल (8), (सुप्रा) के मामले में गजेंद्रगडकर, प्रमुख न्यायधीश की निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

"ऐसे मामलों से निपटने में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब राज्य अपने सेवकों के लापरवाह कृत्यों के कारण होने वाली चोट के कारण होने वाले नुकसान के दावों के खिलाफ प्रतिरक्षा की दलील देता है, तो संप्रभु शक्तियों को संदर्भित रोजगार के क्षेत्र को सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह की याचिका को बरकरार रखने से पहले, अदालत को हमेशा यह पता लगाना चाहिए कि लागू किया गया कार्य एक उपक्रम या रोजगार के दौरान किया गया था जो प्रत्यायोजित संप्रभु शक्ति के प्रयोग को संदर्भित करता है।

28. इस प्रकार ऐसे मामलों में राज्य के दायित्व के संबंध में बताई गई कानूनी स्थिति विवादित नहीं रही है और अन्यथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दृढ़ता से तय की जा रही है। हालांकि, विभिन्न मामलों में इस सिद्धांत के वास्तविक अनुप्रयोग में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में विवाद इस सवाल के आसपास केंद्रित होता है कि क्या शिकायत

[21] ए. आई. आर. 1962 ए. सी. 933.

की गई कार्रवाई वास्तव में एक उपक्रम या रोजगार के दौरान की गई थी जो संप्रभु शक्तियों या प्रत्यायोजित संप्रभु शक्तियों के प्रयोग के लिए संदर्भित है। इस स्तर पर यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि एक संप्रभु अधिनियम क्या है।

29. भागलपुर के जिला बोर्ड बनाम बिहार प्रांत[22], यह देखा गया है कि सरकारी कार्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है; (1) राज्य का अधिनियम, (2) सरकारी गतिविधियाँ या संप्रभु शक्तियां, और (3) वाणिज्यिक गतिविधियाँ। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्य, अर्थात्, सरकारी गतिविधियाँ या संप्रभु शक्तियां, वे हैं जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा या उसके निर्देशन में संप्रभु प्राधिकरण या व्यक्तियों द्वारा कानूनी रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें संप्रभु प्राधिकरण उन शक्तियों को सौंप सकता है। हालांकि, उस निर्णय में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि संप्रभु कार्य या शक्ति का क्या अर्थ है।.

30. संप्रभुता की अवधारणा गुरुद्वारा साहिब सिरी तेग बहादुर गजा बनाम पियारा सिंह[23], पेप्सू उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आई थी। हालांकि एक अलग संबंध में हैं और इससे निपटते हुए विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने यह देखने के बाद कि संप्रभुता, जैसा कि हिबर्ट ने अपने न्यायशास्त्र में देखा है, एक मानवीय संस्था है और ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, एक पूर्ण परिभाषा को स्वीकार नहीं करता है, जो श्री हिबर्ट द्वारा न्यायशास्त्र पर उनकी पुस्तक के पृष्ठ 58 पर दी गई परिभाषा के विपरीत है। जो इन शब्दों में है:-

"'संप्रभु' शब्द का अर्थ एक राजनीतिक श्रेष्ठ है जो किसी अन्य राजनीतिक वरिष्ठ के अधीन नहीं है।

इसके बाद प्रोफेसर हॉलैंड के न्यायशास्त्र का संदर्भ दिया गया जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 50 पर कहा है-

उन्होंने कहा, 'सत्तारूढ़ हिस्से की संप्रभुता के दो पहलू हैं. यह 'बाहरी' है क्योंकि इसके बिना सभी नियंत्रण से स्वतंत्र है; 'आंतरिक' सभी कार्यों पर सर्वोपरि है।

[22] ए.आई.आर 1954 पटना 529.

[23] ए.आई.आर. 1953 पेप्सू 1.

31. हमारे देश के संविधान के तहत, जो अब एक कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। राज्य स्वयं को उन कार्यों तक सीमित नहीं रख रहा है जो पुराने दिनों में कानून और व्यवस्था, कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने और देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए संप्रभु में निहित थे, बल्कि लगातार बढ़ते व्यापार व्यवसाय और वाणिज्यिक उद्यमों, औद्योगिक उपक्रमों और कल्याणकारी गतिविधियों में संलग्न हैं, जिन्हें अब तक सरकार या संप्रभु के आवश्यक कार्यों या विशेषताओं के रूप में नहीं माना जाता था। ऐसे कार्य जो सरकार के व्यापारिक, औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से अपने संप्रभु कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां निजी व्यक्तियों के लिए खुली हैं और उनके द्वारा अच्छी तरह से की जा सकती हैं। हालांकि, प्रशासन से जुड़े कार्य, जिसमें राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था और शांति बनाए रखना, साथ ही बाहरी आक्रमण को पूरा करना शामिल है, ऐसे हैं जो राज्य अकेले कर सकता है और वे, सभी युगों में और सरकारों के सभी रूपों में, चाहे राजशाही हो या लोकतांत्रिक, संप्रभु प्राधिकरण के रूप में अकेले सरकार के आवश्यक कार्य माने गए हैं।

32. संप्रभु अधिनियम या राज्य की शक्ति की कोई सटीक परिभाषा हमारे सामने नहीं रखी गई है। यह विवादित नहीं है, और यह नहीं हो सकता है कि राज्य के संप्रभु कार्यों में सेना का रखरखाव, कानून और व्यवस्था के संरक्षण और देश के उचित प्रशासन के लिए पुलिस सहित विभिन्न विभागों की स्थापना और न्याय के प्रशासन के लिए मशीनरी आदि शामिल हैं। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने राज्य की संप्रभु शक्तियों को परिभाषित करके शुरू किया जो देश के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं और ऐसे कार्य जो सक्षम विधायी प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किए जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि क़ानून व्यापार या वाणिज्यिक उपक्रमों और राज्य के अन्य गैर-संप्रभु कार्यों के संबंध में विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों को शक्ति भी प्रदान कर सकता है, हालांकि, उन्होंने अपनी दलील को संशोधित किया और तर्क दिया कि संप्रभु शक्तियां वे हैं जो एक क़ानून से प्रवाहित होती हैं लेकिन सरकार की व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ी नहीं होती हैं। हालांकि, प्रतिवादियों

की ओर से पेश हुए हरियाणा के महाधिवक्ता ने आग्रह किया कि "संप्रभु शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनका उपयोग संप्रभु या एक संप्रभु द्वारा प्रत्यायोजित निजी व्यक्ति द्वारा उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए किए जाने के अलावा कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता है"। प्रायद्वीपीय और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी के मामले (12) (सुप्रा) में पीकॉक, प्रमुख न्यायधीश की यही उक्ति है, जिसे मेसर्स कस्तूरी लाल के मामले (8) में सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है।

33. यह सच है कि आमतौर पर संप्रभु राज्य के कार्यों को संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा एक क़ानून या नियमों और विनियमों द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अधिकार के आधार पर किया जाता है, लेकिन हम श्री कौशल से सहमत हैं कि इस तरह के प्राधिकरण का प्रयोग एक क़ानून द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण तक सीमित नहीं होना चाहिए। श्री कौशल ने ठीक ही कहा है कि विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों को विभिन्न संविधियों द्वारा प्रदत्त सरकारी शक्तियों के अलावा अन्य सरकारी शक्तियां हैं जिनका उपयोग राज्य के मामलों के संबंध में किया जा सकता है और जिन्हें कार्यकारी शक्तियों के रूप में जाना जाता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 से स्पष्ट है। पूर्व में यह निर्धारित किया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जबकि बाद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य को कानून बनाने की शक्ति है। हमारे संविधान की योजना के तहत, विधायी और कार्यकारी कार्य अलग-अलग हैं और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्यकारी शक्ति के अलावा, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विभिन्न संविधियों या नियमों के तहत कार्यपालिका को सौंपा जा सकता है, कार्यपालिका, राज्यों और केंद्र दोनों में, अन्य कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 53 से स्पष्ट है जो यह प्रावधान करता है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह कानून के तहत देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी है। अनुच्छेद 352, जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, आगे यह स्पष्ट करता है कि कुछ मामलों में और कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यों का उपयोग करता है जो आमतौर पर

एक उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री कुलदीप सिंह का यह तर्क कि जब तक कोई कार्य या कोई कार्य किसी क़ानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक इसे सरकारी कार्य या राज्य की संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है। किसी भी मामले मेंयह विवाद से परे है कि सेना की स्थापना और रखरखाव एक प्राथमिक है, और वास्तव में राज्य या सरकार के सबसे आवश्यक कार्यों में से एक है और तदनुसार, सशस्त्र बलों के रखरखाव और कामकाज से संबंधित कोई भी कार्य इसके किसी भी पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे ऐसे कर्तव्य सौंपे गए हैं, राज्य के संप्रभु अधिकार का प्रयोग करके किया गया माना जाना चाहिए। हालांकि, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि सेना के रखरखाव या स्थापना या कामकाज के संबंध में सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए सभी कार्यों को संप्रभु अधिनियम कहा जा सकता है। ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित परीक्षण यह है कि क्या किया गया कार्य वह है जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा उसे सौंपी गई संप्रभु शक्ति के बिना किया जा सकता है। यदि वचन पत्र ऐसा है कि कोई निजी व्यक्ति उन कृत्यों में संलग्न नहीं हो सकता है, तो ऐसे कृत्यों को राज्य की संप्रभु शक्ति के संबंध में माना जाना चाहिए।

34. यह आग्रह करते हुए कि ट्रक के चालक द्वारा हमारे समक्ष किए गए मामले में शिकायत की गई घृणित कार्रवाई को राज्य के किसी भी संप्रभु कार्यों का प्रयोग करके नहीं माना जा सकता है, कुलदीप सिंह ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि वाहन चलाना एक ऐसा कार्य नहीं है जिसे विशेष रूप से सेना में कार्यरत व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जा सकता है, लेकिन इसे एक निजी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। इसके संबंध में इस तरह की किसी प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि वाहन को कोई ऐसा व्यक्ति भी चला सकता है जो सेना में कार्यरत नहीं है और वाहन चलाने का कार्य सेना के कार्यों या सरकार के कर्मचारी के लिए कुछ विशिष्ट नहीं है। इस प्रश्न पर कि क्या किसी वाहन के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का कार्य राज्य के संप्रभु कार्यों के प्रयोग में किया गया था, इस पर इस अलग-थलग तरीके से नहीं बल्कि उन तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में विचार किया जाना

चाहिए जिनमें इस कृत्य की शिकायत की गई थी। सही स्थिति की सराहना करने के लिए, इस बिंदु पर विभिन्न तय मामलों से मार्गदर्शन किया जा सकता है, जिस पर अब हम विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

35. सबसे पहले द प्रायद्वीपीय और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के लिए राज्य सचिव (12), में रिपोर्ट किया गया है। जिस पर पहले विस्तार से ध्यान दिया गया है। उस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नौकरों की लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जिन्हें सरकार द्वारा डॉकयार्ड में नियोजित किया गया था और उन्होंने सड़क पर लोहे की फ़नल का एक टुकड़ा इस तरह से गिरा दिया था कि वादी की गाड़ी चला रहे घोड़ों में से एक को चोट लग सके। यह इस निष्कर्ष पर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर सरकार की संप्रभु शक्तियों से जुड़े किसी भी कार्य में संलग्न नहीं थे।

36. राज्य सचिव v. ए. कॉकक्राफ्ट (17) को लोक निर्माण विभाग के एक ठेकेदार द्वारा एक सैन्य सड़क पर लापरवाही से ढेर की गई बजरी के ढेर पर चलने वाले अपने पहियों में से एक से गुजरने वाले एक पहिये से डूबने वाले एक व्यक्ति को लगी चोटों के लिए नुकसान का दावा किया गया था। यह एक सैन्य सड़क थी जो बैरक की ओर जाती थी जहां सैनिकों को रखा गया था। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि वादी के पास राज्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं था, क्योंकि सड़कों, विशेष रूप से एक सैन्य सड़क का प्रावधान और रखरखाव, सरकार के कार्यों में से एक था जो अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता था और यह एक उपक्रम नहीं है जो निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था। प्रायद्वीपीय और ओरिएंटल केस (12) (सुप्रा) सहित विभिन्न मामलों को उद्धृत करने के बाद , शेषगिरी अय्यर, न्यायधीश ने इन शब्दों में मामले का निपटारा किया।:

"सबसे पहले, यह एक स्थानीय बोर्ड या नगर पालिका द्वारा बनाए गए सड़क नहीं है। नतीजतन, यह सख्ती से सरकारी कर्तव्यों के अभ्यास के भीतर है कि इस सड़क को बनाया और बनाए रखा जाता है। दूसरे स्थान पर, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अमेरिका में नगर निगम के समान है, तो भी यह स्पष्ट है कि कंपनी सड़क को अच्छी मरम्मत में विफल रखने में विफल रहने में अपने नौकरों की लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मामला सर बार्न्स पीकॉक द्वारा पी और ओएसएन, कंपनी बनाम राज्य सचिव (12) में सुझाए गए अपवाद के तहत आता है। लोक सेवकों की लापरवाही के लिए दायित्व के विषय पर रूस बनाम राज्य सचिव[24] में विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

37. हरबंस सिंह के मामले (1) (सुप्रा) में, दुर्घटना एक सैन्य ट्रक के चालक की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई, जब वह ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों को भोजन की आपूर्ति करने की सैन्य ड्यूटी में लगा हुआ था। इस न्यायालय की एक खंडपीठ (डी. फलशॉ और मेहर चंद, न्यायधीश) ने कहा कि भारत संघ उत्तरदायी नहीं था। मेहर सिंह, न्यायधीश, न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए, पी. एंड ओ. स्टीम नेविगेशन कंपनी के मामले (12) (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए इस प्रकार देखा गया:

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 2 का कार्य तब किया गया था जब वह ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों को भोजन की आपूर्ति करने में सैन्य ड्यूटी में लगा हुआ था <u>और उस कर्तव्य का पालन करते समय उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरदायी नहीं हो सकती थी और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। प्रतिवादी नंबर 1 की स्थिति इस संबंध में समान है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है।</u>

38. इस निर्णय को बाद में भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था।श्रीमती जसो (3), डी. फलशॉ, जे. (जो स्वयं दोनों पीठों की सदस्य थीं) ने अपनी राय देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हरबंस सिंह के मामले (1) में निर्णय ने उस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि सेना का चालक "एक संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर रहा था और कुछ ऐसा कर रहा था जो निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता था" और कहा:

"उस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि ट्रक सैन्य कर्तव्यों पर लगे सेना के जवानों की जरूरतों की आपूर्ति के लिए चलाया जा रहा था जो नागरिकों द्वारा नहीं किया जा सकता

[24] ए.आई.आर. 1915 मैड. 434.

था।

"यह कहना किसी भी दर पर सुरक्षित है कि उस मामले को इस सामान्य प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि किसी भी मामले में सरकार के खिलाफ नुकसान के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि दुर्घटना में शामिल वाहन किसी सैन्य कर्मचारी द्वारा किसी कर्तव्य या अन्य के प्रदर्शन में संचालित सेना का एक वाहन है।."

39. इससे यह स्पष्ट है कि एक सैन्य कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों को भोजन की आपूर्ति करने का कार्य भारत संघ के संप्रभु कार्यों के संबंध में माना जाता था। जिस मामले में फालशॉ, न्यायमूर्ति (जैसा कि उस समय लॉर्डशिप) ने ऊपर निर्धारित टिप्पणियां की थीं, पूर्ण न्यायाधीश ने कहा कि शिमला में जनरल मुख्यालय तक कोयले के परिवहन में लगे एक सैन्य ट्रक के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए भारत संघ 1 पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, हालांकि चालक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। इस निष्कर्ष पर आने में फालशॉ, न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा:

"किसी डिपो या स्टोर से कोयले से लदे ट्रक को जनरल मुख्यालय की इमारत तक ले जाना एक नियमित कार्य शिमला में, संभवतः कमरों को गर्म करने के उद्देश्य से, एक संप्रभु शक्ति का प्रयोग करके किया गया कुछ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से एक निजी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

40. रूप राम बनाम पंजाब राज्य (2), इस न्यायालय की एक अन्य पूर्ण पीठ ने लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त एक चालक के लापरवाह आचरण से निपटा, जो कुछ सामग्री ले जा रहा था जिसका उपयोग सार्वजनिक राजमार्ग पर एक पुल के निर्माण में किया जाना था। यह कहते हुए कि राज्य को अपने ड्राइवर के लापरवाह कृत्य के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अदालत के लिए बोलते हुए दुलत न्यायमूर्ति ने कहा:

"यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि ट्रक चालक के पास किसी भी कानून या नियम द्वारा उसे सौंपा गया कोई अजीब कर्तव्य था, न ही उसके रोजगार के बारे में कुछ खास था।."

41. ऐसे मामलों में मार्गदर्शन का नियम इस प्रकार कहा गया था:

"दायित्व न केवल उस कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जिसमें नौकर को लगाया गया होगा, बल्कि रोजगार की प्रकृति और निश्चित रूप से, किए गए अपराध की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। केवल यह तथ्य कि यह कार्य सरकारी गतिविधि के दौरान किया गया हो सकता है या नहीं, एक तरह से या दूसरे तरीके से निर्णायक नहीं है।."

42. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की इस दलील को खारिज करते हुए कि राज्य का लोक निर्माण विभाग, जिस अर्थ में ट्रक का था, इस अर्थ में एक वाणिज्यिक विभाग नहीं था कि यह लाभ कमाने से संबंधित नहीं था, विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

उन्होंने कहा, 'मेरी राय में यह मामला मौजूदा मामले में जिस घृणित कृत्य की शिकायत की गई है, उससे बहुत दूर है, जिससे कोई मदद नहीं मिल सकती.'

43. राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती विद्यावती (21), जो प्रश्न उठा वह एक जिले के कलेक्टर के आधिकारिक उपयोग के लिए राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली जीप के तेज और लापरवाही से चलाने के लिए राज्य के दायित्व के बारे में था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक पैदल यात्री को घातक चोटें आईं जब जीप को मरम्मत के बाद कार्यशाला से लाया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि राजस्थान राज्य अपने दायित्व से बच नहीं सकता है क्योंकि केवल यह तथ्य कि कार को कलेक्टर के उपयोग के लिए बनाए रखा जा रहा था, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में, मामले को उन मामलों की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था जहां नियोक्ता की परोक्ष देयता उत्पन्न हो सकती थी, भले ही कार का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था। राज्य का। संविधान के अनुच्छेद 300 पर भरोसा करते हुए इस विषय पर केस-लॉ की समीक्षा पर, सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, संप्रभु को अपराध या अनुबंध में मुकदमा दायर करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, और भारत में सामान्य कानून प्रतिरक्षा कभी संचालित नहीं होती है। अब जब हमने अपने संविधान के अनुसार, सरकार का एक गणतांत्रिक

रूप स्थापित कर लिया है और इसका एक उद्देश्य अपनी विभिन्न औद्योगिक और अन्य गतिविधियों के साथ एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें नौकरों की एक बड़ी सेना को नियोजित किया गया है, तो सिद्धांत रूप में या सार्वजनिक हित में इसका कोई औचित्य नहीं है कि राज्य को अपने सेवक के घृणित कृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जब यूनाइटेड किंगडम में आम कानून के आधार पर क्राउन के पक्ष में प्रतिरक्षा का नियम अपने जन्म की भूमि से गायब हो गया है, तो कोई कानूनी वारंट नहीं है कि इस देश में इसकी कोई वैधता है, खासकर संविधान के बाद। जैसा कि इस मामले में कार्रवाई का कारण संविधान के लागू होने के बाद उत्पन्न हुआ, हमारी राय में, यह केवल पुराने स्थापित नियम को मान्यता देना होगा, जो कम से कम 100 वर्षों से अधिक पुराना है, यदि हम राज्य के परोक्ष दायित्व को बनाए रखते हैं।."

44. सत्यवती बनाम भारत संघ[25] मामले में, तथ्य यह था कि एक सेना चालक, जिसे एक वाहन के साथ हिरासत में लिया गया था, अपनी वापसी के बारे में गार्ड रूम को रिपोर्ट करने गया था और अपने वाहन को पार्क करने ही वाला था, उसने भारतीय वायु सेना के एक स्थायी कमीशन अधिकारी द्वारा संचालित मोटर साइकिल पर टक्कर मार दी और इस तरह उसे चोटें आईं जिससे उसकी मौत हो गई। भारत संघ ने दलील दी कि वह अपने चालक के क्रूर कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन इस दलील को खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि इस मामले में चालक का कार्य एक उपक्रम या रोजगार के दौरान नहीं किया गया था जो प्रत्यायोजित संप्रभु शक्ति के प्रयोग या यहां तक कि वैधानिक शक्तियों के प्रयोग से बेहतर है। मामले में सबूतों का जिक्र करते हुए एस. के. कपूर, न्यायमूर्ति इन शब्दों में अपने निष्कर्षों को अभिव्यक्त किया:

"प्रदर्शनी पृष्ठ 10 के संदर्भ से पता चलता है कि वाहन हॉकी और बास्केटबॉल टीमों को भारतीय वायु सेना, नई दिल्ली के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारतीय वायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली ले जाने में लगा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मैच खत्म होने के बाद, चालक अपनी वापसी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए गार्ड रूम में गया और दुर्घटना के समय, सब-मोटर

[25] ए.आई.आर. 1967 दिल्ली 98.

टर्मिनस पर वाहन पार्क करने जा रहा था। इस तरह की गतिविधि शायद ही ऊपर उल्लिखित शक्तियों में से किसी के प्रयोग के लिए संदर्भित हो सकती है जो राज्य को प्रतिरक्षा के लिए दावा करने का हकदार बना सकती है।."

45. जोगिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य[26], पंजाब राज्य के स्वामित्व वाली एक पुलिस लॉरी और उसके एक कांस्टेबल द्वारा संचालित पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। राज्य के दो वाहनों के बीच हुई इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, पास में मौजूद एक चरवाहे की जान चली गई। इस न्यायालय ने माना कि राज्य उत्तरदायी था क्योंकि कठोर अधिनियम किसी भी तरह से अपनी संप्रभु शक्तियों के प्रयोग से जुड़ा नहीं था।

46. एक सैन्य अधिकारी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय एक सैन्य ट्रक ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक हाथ-गाड़ी चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भारत संघ की इस दलील को मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने भारत संघ बनाम वरदम्बल और अन्य[27] मामले में खारिज कर दिया था कि वह मुआवजे के दायित्व से मुक्त है, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:

"इस प्रकार न्यायालय को संदेह की स्थिति में छोड़ दिया गया है कि वाहन किस उद्देश्य के लिए लगाया गया था। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि यह सेंट्रल स्टेशन जा रहा था, हम सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि यह एक संप्रभु शक्ति के रूप में संघ के कार्यों के संबंध में था। कभी भी इतनी संभावनाएं थीं। हो सकता है कि मेजर कुरूप कहीं निजी दौरे पर भी गए हों और वापस सेंट्रल स्टेशन लौट रहे हों।."

47. अमूल्य पटनायक बनम उड़ीसा राज्य[28] में यह व्यवस्था दी गई थी कि किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान किए गए घृणित कृत्य के लिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी होगा यदि ऐसा कृत्य राज्य की सार्वभौम शक्तियों के संबंध में किया गया साबित नहीं होता है। तदनुसार, राज्य के एक कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं के वाहन की लापरवाही से ड्राइविंग

[26] 1969 पी. एल. आर. 85.

[27] 969 ए.सी.जे. 220.

[28] ए.आई.आर. 1967 उड़ीसा 116.

के लिए प्रतिरक्षा के दावे को खारिज कर दिया गया था। उस मामले में ए.एस.आई. प्रशिक्षुओं को एक पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था जब चालक के उतावलेपन के कारण यह एक पेड़ से टकरा गई।.

48. यद्यपि किसी राज्य के संप्रभु कार्यों को कहीं भी व्यापक रूप से नहीं गिना गया है और न ही संप्रभु कार्यों का गठन करने की कोई आधिकारिक परिभाषा है, ऊपर देखे गए विभिन्न प्राधिकरणों के अनुपात की समीक्षा से, मार्गदर्शन के कुछ नियम, जो अच्छी तरह से तय प्रतीत होते हैं, उभरते हैं और उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है:

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 (1) के तहत, भारत संघ और हमारे गणराज्य में राज्यों का अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए मुकदमा दायर करने के लिए समान दायित्व है जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था।

(2) स्टीम नेविगेशन कंपनी (12) (सुप्रा) में वर्णित इस दायित्व की प्रकृति और सीमा, और कस्तूरी लाल के मामले (8) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा आधिकारिक रूप से तय की गई है, यह है कि भारत संघ और राज्य सरकार की सेवा में नौकरों की लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं, यदि लापरवाही ऐसी है जो एक साधारण नियोक्ता को उत्तरदायी बनाती है।

(3) कि ऊपर उल्लिखित नियम को ध्यान में रखते हुए, सरकार उत्तरदायी नहीं है यदि शिकायत किए गए कठोर अधिनियम को उसके सेवक द्वारा अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है, जिसके द्वारा हमारा मतलब उन शक्तियों से है जो संप्रभु अधिकारों के प्रत्यायोजन के आधार पर एक संप्रभु या किसी व्यक्ति के अलावा कानूनी रूप से प्रयोग नहीं की जा सकती हैं।

(4) सरकार अपने सेवकों या एजेंटों के उन घृणित कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है जो उसके संप्रभु कार्यों के प्रयोग में या ऐसे लोक सेवकों को सौंपी गई संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए साबित नहीं हुए हैं।

(5) केवल यह तथ्य कि जिस कृत्य की शिकायत की गई है, वह एक लोक सेवक द्वारा अपने

रोजगार के दौरान किया गया था, सरकार को इस तरह के कृत्य के कारण हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(6) जब राज्य अपने सेवकों के लापरवाह कार्य के कारण होने वाली चोट से होने वाले नुकसान के लिए प्रतिरक्षा के खिलाफ प्रतिरक्षा का अनुरोध करता है, तो संप्रभु शक्तियों को संदर्भित रोजगार के क्षेत्र को सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह की याचिका को बरकरार रखने से पहले, न्यायालय को हमेशा यह पता लगाना चाहिए कि लागू किया गया कार्य एक उपक्रम या रोजगार के दौरान किया गया था जो प्रत्यायोजित संप्रभु शक्तियों के प्रयोग के लिए संदर्भित है।

(7) सरकार के संप्रभु कार्यों और जो संप्रभु नहीं हैं, के बीच एक वास्तविक और स्पष्ट अंतर है, और बाद की श्रेणी में आने वाले कुछ कार्य व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय और औद्योगिक उपक्रमों से जुड़े हैं।

(8) जहां वह रोजगार जिसमें कठोर कार्य किया जाता है, ऐसा है जिसमें एक निजी व्यक्ति भी संलग्न हो सकता है, इसे एक संप्रभु कार्य या राज्य के प्रत्यायोजित संप्रभु कार्यों के दौरान किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है।

(9) तथ्य यह है कि वाहन, जो दुर्घटना में शामिल है, सरकार के स्वामित्व में है और उसके नौकर द्वारा संचालित है, सरकार को इसकी तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। यह भी साबित किया जाना चाहिए कि जिस समय दुर्घटना हुई, वाहन चलाने वाला व्यक्ति राज्य के संप्रभु कार्य, या ऐसे प्रत्यायोजित प्राधिकरण के निर्वहन में कार्य कर रहा था।

(10) यद्यपि सेना का रख-रखाव भारत संघ का एक संप्रभु कार्य है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सेना के किसी कर्मी द्वारा किए गए किसी भी घृणित कार्य के लिए संघ सभी दायित्वों से मुक्त है।

(11) यह निर्धारित करने में कि प्रतिरक्षा के दावे की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं,

अधिनियम की प्रकृति, जिस लेनदेन के दौरान यह किया गया है, इसे करने वाले व्यक्ति के रोजगार की प्रकृति और इसके लिए अवसर, सभी पर विचार किया जाना चाहिए।

49. इन सिद्धांतों के प्रकाश में, अब हम उस मामले के तथ्यों की जांच करते हैं जो हमारे सामने है। अधिकरण ने निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध पाया है और हमारे समक्ष उन पर कोई विवाद नहीं है; वास्तव में, पूरा तर्क इस धारणा पर आगे बढ़ा है कि ये तथ्य सही हैं।

50. अमरीक सिंह को घायल करने वाला ट्रक सेना का ट्रक था। इसे सेना का एक ड्राइवर चला रहा था, जिसे दिन भर ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों की जांच के लिए तैनात किया गया था। यह उस कर्तव्य में लगा हुआ था जब यह दुर्घटना का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को चोटें आईं। यह निर्णय लेने में जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या दुर्घटना राज्य के संप्रभु कार्यों के निर्वहन के दौरान हुई थी, वह यह है कि क्या जिस कार्य में ट्रक का चालक लगा हुआ था, वह किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों की जांच के लिए केवल एक सैन्य व्यक्ति को तैनात किया जा सकता है। यह उस उद्देश्य के लिए था कि सेना के वाहन को उस व्यक्ति के निपटान में रखा गया था जिसे इस ड्यूटी पर रखा गया था और वह खुद वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चलाता था। जैसा कि सबूतों से पता चला, यह तब था जब वह इतना आगे बढ़ रहा था कि उसने दुर्घटना का कारण बना। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिस मामले से हम निपट रहे हैं, वह उन मामलों से काफी अलग है जिनसे इस न्यायालय का निर्णय, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित है। वास्तव में, सरकार के दृष्टिकोण से यह उस मामले की तुलना में अधिक मजबूत मामला है जिसके साथ इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश हरबंस सिंह के मामले (1) में विचार कर रहे थे, जिसमें चालक सेना के कामकों को भोजन वितरित करने के लिए ड्यूटी पर था। उस कर्तव्य को राज्य के संप्रभु कार्यों का हिस्सा माना जाता था। उस स्थिति में, संभवतः यह आग्रह किया जा सकता है कि सेना के कर्मियों को भोजन वितरित करने का काम सेना के अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जा

सकता है क्योंकि ड्यूटी पर तैनात सेना के कर्मियों की जांच एक ऐसा कार्य है जो सेना के अनुशासन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और यह केवल सशस्त्र बलों के एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है। वह भी उस बल के ऐसे सदस्य द्वारा जो इस तरह के कर्तव्य के बारे में विस्तृत है और उस कार्य का निर्वहन करने के लिए सशक्त है।

51. जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में देखा गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि सिपाही मान सिंह, जिनके सैन्य ट्रक के तेज और लापरवाही से चलाने के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को चोटें आई थीं, उस दिन ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मियों की जांच करने के लिए ड्यूटी पर थे। हमारे समक्ष बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने हालांकि, उस स्वीकारोक्ति से बाहर निकलने का प्रयास किया और आग्रह किया कि अंबाला के छावनी क्षेत्र में उस दिन ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों की जांच करना सिपाही मान सिंह के कर्तव्य का हिस्सा नहीं था, और किसी भी मामले में ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए गए सबूत यह साबित करने के लिए गए कि दुर्घटना के समय वह नहीं था। सैन्य कर्मियों की जांच के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन निगार सिनेमा में सशस्त्र बलों के कुछ सदस्यों को छोड़ने के बाद लौट रहे थे। दूसरी ओर, एडवोकेट-जनरल ने इन दावों का जोरदार खंडन करने के अलावा, आग्रह किया है कि सिपाही मान सिंह को वास्तव में, और उस दिन सैन्य कर्मियों की जांच करने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया था। इस संबंध में उन्होंने भारतीय सेना अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लेख किया है। ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आग्रह किया जा सकता है और चूंकि वे मुख्य रूप से तथ्य के प्रश्नों से संबंधित हैं, इसलिए हम उन पर नहीं जाना चाहेंगे।

52. विभिन्न प्राधिकरणों की समीक्षा से उभरने वाले कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम कानूनी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो इस आदेश के शुरुआती भाग में निर्धारित किया गया है, नकारात्मक में। हमारी राय में, सैन्य पुलिस के एक सदस्य द्वारा सेना के वाहन के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को लगी चोटों के लिए भारत संघ को

जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जो उसे सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मामले के इस दृष्टिकोण में अपील को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

डी. के. महाजन, न्यायमूर्ति –(53) मैं इससे पूर्णत सहमत हूं, लेकिन सुझाव देता हूं कि इस संबंध में आवश्यक विधान अधिनियमित किया जाए।

पी. सी. पंडित, न्यायमूर्ति – (54) मैं प्रस्तावित आदेश से सहमत हूं कि अपील को खारिज कर दिया जाए, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

एच.आर. सोढ़ी, न्यायमूर्ति –(55) मैं भी सहमत हूं कि अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाए। लागत के लिए।

बी.आर. तुली, न्यायमूर्ति –(56) मैं अपने विद्वान भाई गुरदेव सिंह जे द्वारा दर्ज किए गए आदेश और तर्क से सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा